भारत सरकार
रेल मंत्रालय

राज्य सभा
11.02.2022 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1268 का उत्तर

राजस्थान में रेल संबंधी कार्य

1268. श्री नीरज डांगीः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान में रेल लाइनों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण से संबंधित कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षो के दौरान राजस्थान में रेल लाइनों के दोहरीकरण और विद्युतीकरण के लिए आवंटित की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

राजस्थान में रेल संबंधी कार्य के संबंध में 11.02.2022 को राज्य सभा में श्री नीरज डांगी के अतारांकित प्रश्न सं. 1268 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित **विवरण**

(क) और (ख): रेल परियोजनाएं क्षेत्रीय रेल-वार स्वीकृत की जाती हैं न की राज्य-वार क्योंकि भारतीय रेल की परियोजनाएं राज्य की सीमाओं के आर-पार फैली होती हैं। बहरहाल, 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार, 2,522 कि.मी. कुल लंबाई को कवर करने वाली 27,651 करोड़ रु. की लागत वाली 12 दोहरीकरण परियोजनाएं योजना/स्वीकृति/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 142 कि.मी. लंबाई का कार्य पूरा कर लिया गया है। मार्च, 2021 तक 4400 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।

राजस्थान राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली 3357 कि.मी. कुल लंबाई को कवर करने वाली 16 विद्युतीकरण परियोजनाएं भी योजना/स्वीकृति/कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

राजस्थान राज्य, भारतीय रेल के उत्तर रेलवे, पश्चिम रेलवे उत्तर पश्चिम रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, और उत्तर मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। निधियों के आबंटन और व्यय का परियोजना-वार और जोनल रेलवे-वार ब्यौरा भारतीय रेलवे की वेबसाइट अर्थात् www.indianrailways.gov.in >Ministry of Railways >Railway Board>About Indian Railways>Railway Board Directorates >Finance(Budget), Pink Book (year)> Railway wise Works Machinery and Rolling Stock Programme पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया है।

वर्ष 2014 से अवसंरचनात्मक परियोजनाओं हेतु बजट आबंटन में काफी वृद्धि हुई है। 2014-19 के दौरान, राजस्थान राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए औसत वार्षिक बजट आबंटन को 2009-14 के दौरान 682 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2951 करोड़ रुपए प्रति वर्ष किया गया है, जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट परिव्यय की तुलना में 333% अधिक है। इन आबंटनों को वित्त वर्ष 2019-20 में बढ़ाकर 4686 करोड़ रुपए (वर्ष 2009-14 के औसत वार्षिक बजट आबंटन से 587% अधिक) किया गया है और वित्त वर्ष 2020-21 में 4582 करोड़ रुपए (वर्ष 2009-14 के औसत वार्षिक बजट आबंटन से 572% अधिक) किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इन परियोजनाओं हेतु अभी तक के उच्चतम बजट परिव्यय 6006 करोड़ रुपये मुहैया कराया गया है जो 2009-14 के औसत वार्षिक बजट परिव्यय (682 करोड़ रुपए प्रति वर्ष) की तुलना में 781% अधिक है।

वर्ष 2014-21 के दौरान, राजस्थान राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाले 1947 किमी खंडों (176 कि.मी. नई लाइन, 637 कि.मी. आमान परिवर्तन कार्यों और 1134 कि.मी. की दोहरीकरण परियोजनाएं) को 278.14 किमी प्रति वर्ष की औसत दर से पूरा किया गया है, जो कि वर्ष 2009-14 के दौरान औसत रूप से पूरा किए गए कार्य (159.6 कि.मी. प्रति वर्ष) से 74% अधिक है।

(ग): रेलवे परियोजना(ओं) का समय से पूरा होना राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के प्राधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, बाधक जनोपयोगी सेवाओं की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थिति, परियोजना साइट के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु स्थिति को ध्यान में रखते हुए परियोजना विशेष की साइट के लिए वर्ष में कार्य के महीनों की संख्या, आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और ये सभी कारक परियोजना के समापन समय को प्रभावित करते हैं। अतः इस स्तर पर परियोजना(ओं) के समापन हेतु किसी समय सीमा की पुष्टि नहीं की जा सकती है। बहरहाल, भारतीय रेल द्वारा परियोजनाओं के शीघ्र समापन हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

******